उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 अंक 1 1-15 जनवरी 2021 ₹ 20/-

बलूचिस्तान में सुन्नियों ने खेली शियाओं के खून की होली

- औरंगाबाद का नाम बदलने पर विवाद
- अफगान फौजियों पर हमले में चीन का हाथ
- सऊदी अरब में पहली बार संगीत और अभिनय के लिए लाइसेंस
- विदेशी तब्लीगियों की स्वदेश वापसी का रास्ता साफ

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष: 011-26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक-प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी-51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली-110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए-102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020 मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

औरंगाबाद का नाम बदलने पर विवाद 04
ओवैसी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सक्रिय 07
मुस्लिम नेताओं के निशाने पर संघ प्रमुख भागवत 10
दिल्ली के कब्रिस्तानों में लूट पर रोक 13
हिन्दू धर्म के अपमान पर मुस्लिम कॉमेडियन गिरफ्तार 14

विश्व

बलूचिस्तान में सुन्नियों ने खेली शियाओं के खून की होली 15
बाली बम धमाकों का मास्टरमाइंड रिहा 19
अफगान फौजियों पर हमले में चीन का हाथ 21
अफगानिस्तान में बम वर्षा से एक ही परिवार के 18 लोग मरे 21
सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले मैसेज शेयर करने पर मृत्युदंड 22

पश्चिम एशिया

सऊदी अरब और कतर के संबंधों में सुधार से अरब जगत में नई शुरुआत 23
सऊदी अरब में पहली बार संगीत और अभिनय के लिए लाइसेंस 25
अमेरिका द्वारा हूती संगठन को आतंकवादी संगठन का दर्जा 26
विमान दुर्घटना में मरने वालों को ईरान मुआवजा देगा 26
जनरल सुलेमानी की पहली बरसी 27
अलकायदा का नया अड्डा ईरान 28

अन्य

मुस्लिम द्वारा शिव मंदिर के निर्माण का उद्घाटन 29
तुर्की में पूर्व जनरलों को उम्र कैद 29
अमेरिका द्वारा अरब देशों को अस्त्र-शस्त्रों की बिक्री 29
विदेशी तब्लीगियों की स्वदेश वापसी का रास्ता साफ 30
इजरायल जाने से इनकार करने पर विमान चालक निलंबित 30
कुवैत के मंत्रिमंडल का त्यागपत्र 30

सारांश

महाराष्ट्र में नगर निगम और स्थानीय निकाय के चुनावों की धमक शुरू होते ही नगरों के नाम बदलने की भी राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने का जो वायदा किया था अब वह उसे कार्यान्वित करने का प्रयास कर रही है। इसका खुलकर विरोध महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास आघाडी में शामिल कांग्रेस ने किया है। इसका कारण यह है कि कांग्रेस यह महसूस करती है कि मुसलमानों के एक वर्ग में मुगल बादशाह औरंगजेब काफी लोकप्रिय है और अगर कांग्रेस उसके नाम पर रखे गए नगर का नाम बदलने का विरोध नहीं करती है तो उसके कारण महाराष्ट्र का मुस्लिम वोट बैंक उसके हाथ से खिसक जाएगा। शायद यही कारण है कि वर्तमान सरकार का समर्थन करने वाली समाजवादी पार्टी ने भी औरंगाबाद नगर का नाम बदलने का विरोध किया है। इस विवाद के कारण महाराष्ट्र सरकार के लिए संकट पैदा होने की संभावना बढ़ गई है।

हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत ने एक पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा था कि देशभक्ति हिंदुओं के डीएनए में है। कोई भी हिन्दू देशद्रोही हो ही नहीं सकता। उनका यह कथन मुस्लिम नेताओं को रास नहीं आया। वहाबी संगठन जमीयत-ए-उलेमा हिंद के महामंत्री अब्दुल हमीद नोमानी ने इसका सख्त विरोध किया है और इसे गांधी जी की अवधारणा के खिलाफ बताया है। इसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी भी भागवत जी को अपना निशाना बनाने से बाज नहीं आए। परेशानी की बात यह है कि इस्लाम में वतन परस्ती या वतन की कोई कल्पना ही नहीं है। कुरान और हदीस के अनुसार पूरी दुनिया मुसलमानों का वतन है और हर मुसलमान उनका हमवतन। इस्लाम को 'मिल्लत' और 'उम्माह' के सिद्धांतों में ही आस्था है।

अमेरिका मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों को विभाजित करने में सफल हो रहा है। अमेरिकी प्रयासों के कारण इन मुस्लिम देशों में इजरायल का असर तेजी से बढ़ रहा है। अब तक छह मुस्लिम देश इजरायल को मान्यता दे चुके हैं। अमेरिका का निशाना ईरान है। कतर को ईरान से अलग करने में अमेरिका सफल रहा है। चार वर्ष पूर्व सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों ने कतर की नाकेबंदी और उसका बहिष्कार किया था। मगर अब कुवैत और अमेरिका के दबाव पर उसे खत्म कर दिया गया है। मुस्लिम जगत में हुए इस घटनाक्रम के बाद ईरान अलग-थलग पड़ गया है।

पाकिस्तान में शियाओं का उत्पीड़न जारी है। हाल ही में बलुचिस्तान में इस्लामिक स्टेट के जिहादियों ने 11 निर्दोष शियाओं की सामूहिक रूप से हत्या कर दी। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में शियाओं के धरने और प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पहले तो इस मामले को दबाने का प्रयास किया मगर जब जनाक्रोश ने भीषण रूप ले लिया तो उन्हें मौके पर जाकर मृतकों के परिजनों की सातों मांगों को स्वीकार करना पड़ा। पाकिस्तान में जिस तरह से विभिन्न मुस्लिम सम्प्रदायों में हिंसा बढ़ रही है, उसके कारण पाकिस्तान का विघटन होने की संभावना बढ़ गई है।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। उनका लक्ष्य इन राज्यों के आने वाली विधान सभा चुनावों में भाग लेने का है। पश्चिम बंगाल में तीस प्रतिशत मुस्लिम मतदाता तृणमूल कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हैं। अब उनको विभाजित करने के लिए ओवैसी दरगाहों और पीर फकीरों के दरबारों में हाजिरी दे रहे हैं। उनकी इस हरकत से ममता बनर्जी और कांग्रेस दोनों परेशान हैं।

राष्ट्रीय

औरंगाबाद का नाम बदलने पर विवाद

महाराष्ट्र में नगर निगम और स्थानीय निकायों के चुनाव की चर्चा गरम होते ही नगरों के नाम बदलने का भी विवाद तेज हो गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (1 जनवरी) के अनुसार महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास आघाडी में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने के मामले पर तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के मंत्री बालासाहेब थोराट ने कहा है कि कांग्रेस नगरों के नाम बदलने में विश्वास नहीं रखती। इसलिए हम नाम बदलने के किसी भी कार्यवाही का विरोध करेंगे। क्योंकि यह संविधान के साथ धोखा होगा। थोराट नगर निगमों और स्थानीय निकायों के चुनावों की तैयारियों के सिलसिले में कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए औरंगाबाद आए थे। उन्होंने कहा कि अगर औरंगाबाद नगर का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव उनके सामने आता है तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि नाम बदलने में आम लोगों का विकास नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस तरह की राजनीति कर रही है। हम उसमें विश्वास नहीं रखते। उन्होने कहा कि महाराष्ट्र में तीन दल सत्ता में हैं और औरंगाबाद का नाम बदलना हमारे कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है।

इसी समाचारपत्र ने 5 जनवरी के अंक में एक समाचार प्रकाशित किया है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि शिवसेना को औरंगाबाद का नाम बदलने की बजाय पुणे का नाम बदलकर संभाजी नगर रख लेना चाहिए। औरंगाबाद का नाम बदलने का विरोध सबसे पहले महाविकास आघाडी में शामिल कांग्रेस ने किया था। जिस पर भाजपा ने शिवसेना को निशाना बनाते हुए उससे मांग की थी कि वह औरंगाबाद का नाम बदलने के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। इसके जवाब में शिवसेना के प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि महाराष्ट्र का नाम ही शिवाजी महाराज के नाम पर रख दिया

जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी औरंगाबाद का नाम बदलने का विरोध किया है और भाजपा को अपना निशाना बनाया है। चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए कई नगरों के नाम बदलने की मांग जोर पकड़ रही है। महाविकास आघाडी की सरकार का समर्थन करने वाली समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र शाखा के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने भी नगरों के नाम बदलने का विरोध किया है और कहा है कि नगरों के नाम बदलने से किसी का पेट नहीं भरता। अगर नगरों का नाम ही रखना है तो नए नगर बसाए जाने चाहिए। अहमदनगर या औरंगाबाद का एक पुराना इतिहास है उसे जबरन बदलना सरासर गलत है।

इसी समाचार पत्र ने 9 जनवरी के अंक में अपने मुख्य पृष्ठ पर एक समाचार प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने के मुद्दे पर राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। शिवसेना के प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि औरंगजेब सेक्युलर नहीं था। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ महाविकास आघाडी में शामिल तीनों दलों के एजेंडे में सेक्युलर शब्द का कहीं उल्लेख तक नहीं है और जहां तक औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने का सवाल है इसका फैसला तो वर्षों पहले ही हो चुका है। उन्होंने कहा कि जब राज्य में सेक्युलर सरकार थी तब भी मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी होने वाले हर कागज पर औरंगाबाद को संभाजीनगर ही लिखा जाता था। उनके इस बयान पर टिप्पणी करते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने कहा कि संभाजी महाराज हमारे लिए देवता हैं मगर नाम बदलने के मामले में हम खिलाफ हैं। इस संदर्भ में भी हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। हमारी पार्टी का यह प्रयास होगा कि औरंगाबाद का नाम ज्यों का त्यों रहने दिया जाए और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए।

इंकलाब (8 जनवरी) के अनुसार नाम बदलने का विवाद देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। कुछ लोगों ने औरंगजेब लेन का नाम बदलकर गुरु तेगबहादुर लेन रखने की कोशिश की जिसे पुलिस ने विफल बना दिया। पुलिस ने इस संदर्भ में ग्यारह लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार अनुराग भार्गव नामक व्यक्ति के नेतृत्व में ग्यारह लोग इक्ट्ठे हुए थे और वे औरंगजेब लेन की जगह पर गुरुतेग बहादुर लेन को चिपकाने की कोशिश कर रहे थे। जब यह सूचना तुगलक रोड थाने को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भार्गव सहित सभी ग्यारह लोगों को हिरासत में ले लिया। जांच के दौरान पता चला कि अनुराग भार्गव हरियाणा के करनाल का रहने वाला एक वकील है। इससे पहले भी औरंगजेब लेन का नाम बदलने का प्रयास हो चुका है। जब इससे पूर्व औरंगजेब रोड का नाम बदलकर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोड रखा गया था तो उस पर भी विवाद हुआ था।

मुंबई उर्दू न्यूज (2 जनवरी) के अनुसार बेंगलुरु से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने वहां के कुछ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की सड़कों के नामों को बदलने पर जोर दिया है। उन्होंने बेंगलुरु नगरपालिका के आयुक्त एन. मंजूनाथ प्रसाद को एक पत्र लिखकर इस पर विरोध प्रकट किया है कि इन सड़कों का नाम सिर्फ मुसलमानों के नाम पर क्यों रखा गया है? उन्होंने कहा कि यह दृष्टिकोण द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रोत्साहन देता है और यह हिंदुओं तथा मुसलमान दोनों के लिए

खतरनाक है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि गैर-मुसलमान राष्ट्रभक्तों के नाम पर भी सड़कों का नाम रखा जाना चाहिए। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब नगर के इंदिरा नगर में 100 फुट चौड़ी सड़क का नाम नगर निगम ने लोक गायक डॉ. एस.के. करीम खान के नाम पर रखने का फैसला किया। जबकि भाजपा की मांग थी कि इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाए। नगर निगम ने 2006 में इस सड़क का नाम लोक गायक डॉ. करीम खान के नाम पर रखने का फैसला किया था। यह मांग कन्नड समर्थक एक संस्थान ने रखी थी।

इत्तेमाद ने 12 जनवरी के अंक में नगरों के नाम बदलने की तीव्र आलोचना की है और इसे संकुचित साम्प्रदायिक दृष्टिकोण की संज्ञा दी है। समाचारपत्र का कहना है कि देश के पुराने मुस्लिम शासकों के नाम पर बसाए गए नगरों और कस्बों के नामों को बदलने की लंबे समय से साजिश चल रही है। महाराष्ट्र में भले ही भाजपा और शिवसेना के बीच सत्ता को लेकर मतभेद हों मगर वैचारिक दृष्टि से इन दोनों का दृष्टिकोण एक ही है। दोनों का आधार हिंदुत्व है। इसलिए इन दिनों महाराष्ट्र के ऐतिहासिक नगर औरंगाबाद का नाम बदलने की राजनीति गरमा रही है। नाम बदलने का सख्त विरोध होने के बावजूद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कार्यालय की ओर से भेजे जाने वाले कागजों पर औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर लिखा जा रहा है। दरअसल शुरू से ही शिवसेना इस नगर का नाम बदलना चाहती है और यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था। औरंगाबाद का नाम बदलने की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो यह मालूम होगा कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने बहुत पहले औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद 1988 में औरंगाबाद नगर निगम के चुनाव में शिवसेना ने 80 सीटों में से 28 सीटें जीतीं। औरंगाबाद का नाम बदलने के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी थी मगर इस मामले को न्यायालय में चुनौती दी गई। उस समय पूरे मराठवाड़ा में विरोध प्रदर्शन हुए और सर्वोच्च न्यायालय ने नाम बदलने के निर्णय को रद्द कर दिया। औरंगाबाद में जब भी चुनाव की गर्मी शुरू होती है नाम बदलने का मामला भी जोर पकड़ लेता है। इसी तरह हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भाजपा ने हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखने का वायदा किया था।

समाचारपत्र का कहना है कि लोकसभा के चुनाव से पूर्व भाजपा ने 'सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास' का नारा दिया था लेकिन ऐसा महसूस होता है कि यह पार्टी लोगों का विश्वास जीतने में विफल रही है। नामों को बदलने की राजनीति को घटिया राजनीति का नाम दिया जाता है और उसका लक्ष्य मुसलमानों की पहचान को मिटाना है। भाजपा जितनी रुचि नगरों के नाम बदलने में ले रही है अगर वह जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लेती तो यह बेहतर होता। मगर साम्प्रदायिक मनोवृत्ति वाले लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सिर्फ फिरकापरस्ती की आग पर अपनी सियासी रोटियां सेंकना चाहते हैं। लेकिन ऐसी ताकतों को यह याद रखना चाहिए कि नाम बदलने से इतिहास नहीं बदला जा सकता।

ओवैसी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सक्रिय

इंकलाब (5 जनवरी) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के अचानक पश्चिम बंगाल का दौरा करने और वहां पर हुगली में जाकर मुस्लिम सम्प्रदाय में प्रभावी फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और उनके भाई पीरजादा नौशाद सिद्दीकी से मुलाकात करने से राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। एक ओर मुसलमानों में ओवैसी के आने से प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है तो दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस उनके राज्य की राजनीति में सक्रिय होने से परेशान है। भाजपा भी मुस्लिम वोटों के विभाजित होने की संभावनाओं से पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने की संभावनाएं देख रही है। ओवैसी ने अपने सहयोगियों के साथ एक अन्य दरगाह हजरत अबू बकर के मजार पर जाकर हाजिरी दी और फातिहा पढ़ा। इसके साथ ही ओवैसी ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष शहंशाह जहांगीर के साथ भी गुप्त बैठक की, जिसमें राज्य विधान सभा के होने वाले चुनाव के विभिन्न पक्षों पर विचार किया गया। इन मुलाकातों के बाद ओवैसी ने संवादादाताओं को बताया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के नेतृत्व में राज्य विधान सभा के चुनाव में भाग लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल के विकास में फुरफुरा दरगाह की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है। पीर सूफी शेख अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि अब्बास सिद्दीकी जो भी निर्णय करेंगे मैं उनका समर्थन करूंगा। बंगाल के चुनाव के बारे में रणनीति तैयार करना सिद्दीकी का काम है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या सिद्दीकी उनकी पार्टी में शामिल होंगे?

समाचारपत्र का कहना है कि हाल के वर्षों में सिद्दीकी पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के एक बड़े वर्ग में एक प्रभावी नेता के रूप में उभरे हैं। पहले वे तृणमूल कांग्रेस में थे मगर अब वे उससे अलग हो चुके हैं। कुछ महीने पूर्व उन पर कुछ लोगों ने हमला किया था। तब उनके समर्थकों ने

यह आरोप लगाया था कि उन पर यह हमला तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के एक नेता शौकत अली मुल्ला ने अब्बास सिद्दीकी को भाजपा का दलाल बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम वोटों को विभाजित करने के लिए अब्बास सिद्दीकी जैसे लोगों को खरीदकर भाजपा उसका इस्तेमाल कर रही है। बिहार के चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद मजलिस के हौसले बढ़े हैं। हालांकि मुसलमानों के एक बडे वर्ग का विचार है कि कहीं मुस्लिम मतदाताओं के विभाजन के कारण भाजपा पश्चिम बंगाल के शासन को ही न हड़प ले। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता 30 प्रतिशत के लगभग हैं। राज्य के 110 विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हार जीत की कुंजी मुस्लिम मतदाताओं के हाथों में है।

इत्तेमाद (4 जनवरी) के अनुसार मजलिस के पश्चिम बंगाल के सचिव जमीरूल हुसैन ने बताया कि हमने ओवैसी के इस दौरे को इसलिए गुप्त रखा था क्योंकि हमें यह भय था कि उन्हें राज्य सरकार एयरपोर्ट से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देगी। इसलिए वे गुप्त रूप से अब्बास सिद्दीकी से मिलने गए थे। इसके बाद वे फौरन हैदराबाद चले गए। उन्होंने कहा कि पहले यह तय किया गया था कि ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विचार विमर्श हो मगर बाद में ओवैसी ने अचानक इसे रद्द कर दिया और वे कोलकाता पहुंच गए। अब्बास सिद्दीकी खुलकर ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं इसलिए हमने उनका सहयोग लेने का फैसला किया है। यह साफ है कि हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मगर अभी तक यह फैसला नहीं हो पाया है कि वे मजलिस में शामिल होंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे। ओवैसी की गतिविधियों के कारण तृणमूल कांग्रेस में काफी परेशानी है। उसके एक वरिष्ठ नेता और सांसद सौगत रॉय का आरोप है कि मजलिस बीजेपी की एक प्रॉक्सी पार्टी है। ओवैसी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि यहां के मुसलमान बंगाली भाषी हैं इसलिए वे उनके जाल में नहीं आएंगे। यही कारण है कि उन्होंने अब्बास सिद्दीकी को अपने जाल में फंसाने का फैसला किया है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल के मुसलमान ममता बनर्जी के साथ हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की कामयाबी में मुसलमानों की भूमिका महत्त्वपूर्ण थी। लेकिन राज्य के कई मुस्लिम नेताओं का यह ख्याल है कि मजलिस के चुनावी दंगल में उतरने के कारण स्थिति बदल सकती है। वहां पर मजलिस अपने पांव आसानी से फैला सकती है क्योंकि वहां पर मुसलमानों की आबादी 30 प्रतिशत से भी अधिक है। ओवैसी ने ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि उनको मजलिस पर उंगलियां उठाने की बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि लोकसभा के चनुाव में पश्चिम बंगाल से बीजेपी ने क्यों 18 सीटें जीती हैं? उन्होंने इस बात का खंडन किया कि उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। उनका कहना था कि हम एक अलग राजनीतिक पार्टी हैं और हम अपना चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि भारत की राजनीति की मैं लैला हूं और मेरे मजनूं बहुत हैं। सभी मुझे चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक हम यह निर्णय नहीं कर पाए हैं कि हम अपने बलबूते वहां पर चुनाव लड़ेंगे या किसी से गठजोड़ करेंगे। उन्होंने इस आरोप का भी खंडन किया कि बिहार के चुनाव में उनके चुनावी दंगल में उतरने का लाभ एनडीए को हुआ है।

अवधनामा (6 जनवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव को देखते हुए सभी प्रमुख पार्टियों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी मजलिस भी हिस्सा लेने की घोषणा कर चुकी है। हालांकि यह आरोप लगता रहा है कि मजलिस को भाजपा मुस्लिम वोटों के विभाजन के लिए मैदान में उतारती है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसी महीने पूर्वांचल का दौरा करने का फैसला किया है। पूर्वांचल में मुसलमानों की भारी जनसंख्या है। ओवैसी उन्हें शीशे में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरे में वे खासतौर पर मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों के चक्कर लगाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उनका इरादा मुसलमानों के धार्मिक नेताओं का समर्थन प्राप्त करना है। उनकी गतिविधियों से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को परेशानी हो रही है। इससे पूर्व भी वे ओमप्रकाश राजभर की सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से भी मुलाकात कर चुके हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार की तरह बीएसपी भी मजलिस का साथ उत्तर प्रदेश में देगी? मजलिस सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से पहले ही समझौता कर चुकी है।

सियासत (3 जनवरी) ने वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त का एक लेख प्रकाशित किया है जिसमें उन्होंने अमित शाह के इस दावे का उल्लेख किया है कि आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा 200 सीटें जीतने में सफल होगी। उन्होंने दावा किया कि एक वर्ष से भाजपा और संघ के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पैर पसार रहे हैं। यही कारण है कि गत चार वर्षों में तेजी से भाजपा ग्रामीण अंचलों में अपने पैर पसार रही है। उनकी गतिविधियों से तृणमूल कांग्रेस हालांकि परेशान है मगर फिर भी उसका यह दावा है कि भाजपा उसे राज्य की राजनीति से बेदखल नहीं कर सकती। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम बंगाल में इस बार दोनों पार्टियों में कड़ी टक्कर होगी। भाजपा का पूरा जोर इस बात पर है कि तृणमूल कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी मुस्लिम मतदाताओं को विभाजित किया जाए और हिन्दू मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो। बंगाल के नौ जिलों में 184 विधान सभा सीटें हैं जिनमें तृणमूल कांग्रेस का संगठन मजबूत है। इनमें पूर्वी वर्धमान, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, उत्तर चौबीस परगना, नदिया, हुगली, मुर्शिदाबाद, हावड़ा आदि शामिल हैं। मगर अगर भाजपा पूरे पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को धर्म के नाम पर जागृत कर पाती है तो उसके कारण ममता को परेशानी हो सकती है। दोबारा सरकार का कार्यक्रम तृणमूल कांग्रेस पूरी गति से चला रही है। अभी तक ममता बनर्जी के रास्ते में कोई रूकावट नजर नहीं आती। भाजपा के प्रभाव को सीमित करने के लिए ममता बनर्जी ने हाल ही में इमामों की तरह सभी मंदिरों के पुजारियों को भी सरकारी खजाने से मानदेय देने की घोषणा की है।

इंकलाब (13 जनवरी) के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे उत्तर प्रदेश का हाल ही में तूफानी दौरा किया। ओवैसी ने इस दौरे के दौरान कहीं भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं किया। हालांकि उन्होंने वायदा किया था कि वे जौनपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ओवैसी के साथ ओमप्रकाश राजभर भी थे। एक अन्य समाचार के अनुसार ओवैसी ने सराय मीर, आजमगढ़ और फूलपुर, का तूफानी दौरा किया और उन्होंने मजलिस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली से लम्बी मुलाकात की।

मुस्लिम नेताओं के निशाने पर संघ प्रमुख भागवत

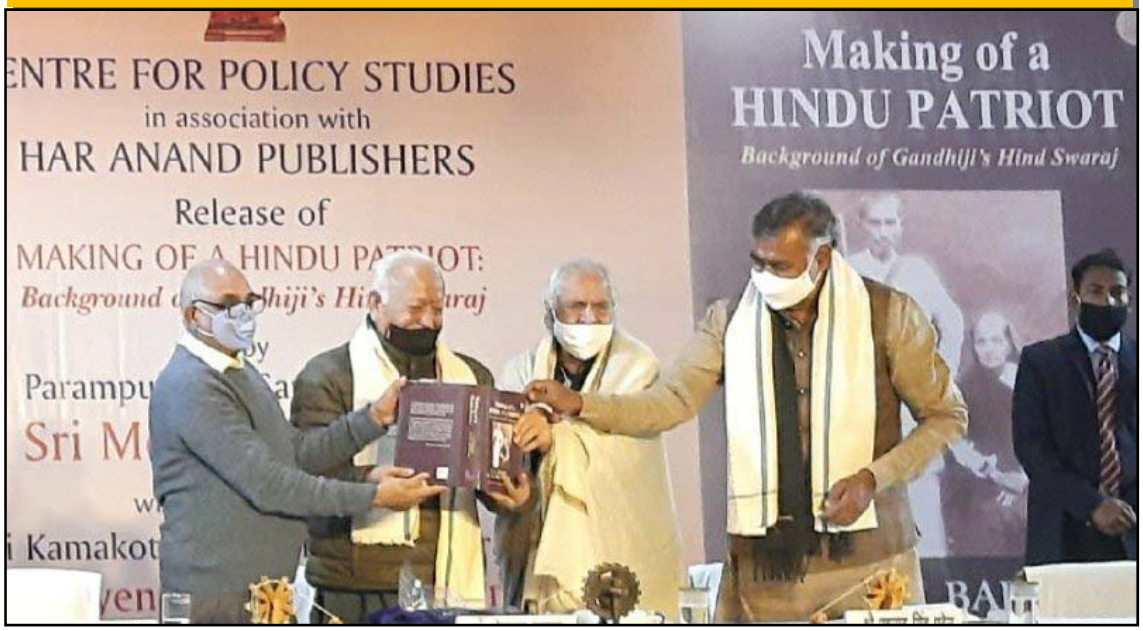

मुस्लिम संगठन जमीयत-ए-उलेमा के महामंत्री मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी ने **इंकलाब** (8 जनवरी) में प्रकाशित एक लेख में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत की आलोचना की है। एक जनवरी को जे. के. बजाज और एम.डी. श्रीनिवास द्वारा लिखित पुस्तक 'Making of a Hindu Patriot : Background of Gandhiji's Hind Swaraj' के लोकार्पण के अवसर पर श्री भागवत ने कहा था कि जो हिन्दू है उसका देशभक्त होना तय है क्योंकि यह उसके डीएनए में है। वह सोया हुआ हो सकता है और उसको जागृत करना होगा। लेकिन कोई हिन्दू हिन्दुस्तान विरोधी नहीं हो सकता। अगर कोई हिन्दू होगा तो वह निश्चित रूप से राष्ट्रभक्त ही होगा। यह उसका बुनियादी स्वभाव है।

नोमानी ने लिखा है कि "राष्ट्रवाद की यह परिभाषा गांधी, नेहरू और अन्य देशभक्त भारतीयों और स्वतंत्रता सेनानियों के दृष्टिकोण के खिलाफ है और संघ तथा हिन्दू महासभा के नकारात्मक राष्ट्रवाद की धारणा के अनुसार है। डॉ. भागवत के इस बयान पर मजलिस के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में टिप्पणी करते हुए सवाल उठाया है कि भागवत जी का गांधीजी के हत्यारे गोडसे के बारे में क्या कहना है? नेल्ली नरसंहार, सिख विरोधी दंगे और गुजरात में हुए कत्लेआम के दोषी व्यक्तियों के लिए भागवत जी का क्या कहना है? राष्ट्रवाद की इस बहस में गोडसे को लाने का साफ मतलब यह है कि ओवैसी साहब असली समस्या को नहीं समझ सके हैं। अगर यह चर्चा होती कि हिन्दू दंगाई और हत्यारे हो सकते हैं कि नहीं, तो अलग बात थी। नेल्ली नरसंहार, गुजरात दंगे और सिख विरोधी दंगों के मुद्दों को उठाना गांधी हत्याकांड के मामले में ज्यादा जानदार होता। इस तरह से ओवैसी ने जानबूझकर असंबंधित मुद्दे को आगे बढ़ाया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और संघ के दूसरे

सरसंघचालक गुरु गोलवलकर ने तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल को जो पत्र लिखा था उसमें कहा गया था कि गांधी हत्या के समय गोडसे का संघ से कोई संबंध नहीं था बल्कि वह हिन्दू महासभा में था इसलिए गांधी हत्याकांड में आरएसएस पर गांधी हत्या का आरोप सिद्ध नहीं हो सका। यही कारण है कि सरसंघचालक श्री गोलवलकर को न्यायालय ने मुक्त कर दिया था। ऐसी स्थिति में ओवैसी का यह सवाल उठाना अर्थहीन है। शायद इसका कारण यह है कि अभी हम इस संदर्भ में तथ्यों को एकत्रित करने में विफल रहे हैं। हालांकि इस संदर्भ में ओवैसी, मौलाना बदरूद्दीन अजमल और अन्य लोग जरूरी अनुसंधान करवा सकते हैं।"

नोमानी का कहना है कि "डॉक्टर भागवत की इस टिप्पणी में यह जरूर सच्चाई है कि महान हस्तियों की व्याख्या कोई भी अपनी दृष्टि से नहीं कर सकता है। गांधी के जीवन का हर पहलू और इतिहास दुनिया के सामने आ चुका है। इसलिए उसके संबंध में कोई भी कुछ कहकर आगे नहीं बढ़ सकता। जानने वाले जानते हैं कि साम्प्रदायिक सद्भावना, अहिंसा और राष्ट्रवाद के संदर्भ में गांधीजी की क्या कल्पना और विचार थे। वे निश्चित रूप से संघ की विचारधारा और दर्शन से मेल नहीं खाते। संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार हिन्दू-मुस्लिम एकता और राष्ट्रीयता की अपनी धारणा के कारण कांग्रेस और गांधीजी की राह से अलग हो गए थे। इस संदर्भ में मैंने एक पुस्तक में डॉ. हेडगेवार के जीवन और उनकी विचारधारा पर काफी विस्तार से चर्चा की है। संघ और हिन्दू महासभा की राष्ट्रीयता की जो कल्पना है वह हिन्दू मुस्लिम एकता के समर्थक नेताओं से बिल्कुल अलग और भिन्न है। उनकी विचारधारा भारतीय परम्परा, अनेकता में एकता के जीवन दर्शन को ध्वस्त कर देती है। संघ भारत में विभिन्न सभ्यताओं के वजूद को स्वीकार नहीं करता और उसका विरोधी है। जबकि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर आदि अनेक राष्ट्र नेताओं की नजर में इस देश में विभिन्न सभ्यताएं मौजूद हैं और वे उन्हें स्वीकार करते हैं तथा उन्हें भारतीय परम्पराओं और विशिष्टताओं में मानते हैं। डॉ. भागवत ने बहुत बुद्धिमता से संघ और हिन्दू महासभा के हिन्दू सम्प्रदाय पर आधारित विशेष दृष्टिकोण के तहत राष्ट्रीयता और देशभक्ति को पेश करने का काम किया है।"

नोमानी ने लिखा है कि "संघ की विचारधारा के अनुसार सिर्फ हिन्दू ही इस देश के असली नागरिक हैं जबकि अन्य सम्प्रदायों से संबंधित लोग देश के नागरिक होने के बावजूद राष्ट्रवाद की परिभाषा के कारण इस देश के राष्ट्रवादी नागरिक नहीं हैं। संघ के अनुसार हिन्दू ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही हिन्दू। मोटे तौर पर इसका यह परिणाम निकलता है कि भारत में सिर्फ हिन्दू ही राष्ट्रवादी हैं। यह दृष्टिकोण बहुत संकुचित और साम्प्रदायिकता पर आधारित आक्रामक दृष्टिकोण है जो कि हिन्दुस्तानी राष्ट्रवाद की सेक्युलर कल्पना से अलग है। मैंने इस संबंध में विस्तृत रूप से एक पुस्तक लिखी है जिसमें इसका विश्लेषण किया है और यह पूछा है कि डॉ. भागवत और इससे पूर्व संघ के सरसंघचालक हिन्दुस्तान के विभिन्न धर्मों और जीवन पद्धतियों को मानने वाले सभी लोगों को हिन्दू या हिन्दुस्तानी क्यों नहीं कहते हैं और वे हिंदुओं को ही राष्ट्रवादी क्यों करार देते हैं? जबकि महात्मा गांधी ने अपनी विख्यात पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा है कि अगर हिन्दू यह समझते हैं कि भारत

में सिर्फ हिंदुओं को ही रहना चाहिए तो वे सपनों की दुनिया में रह रहे हैं। हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ईसाई जिन्होंने भारत को अपना देश बना लिया है वे भी इस देश के बराबर के नागरिक हैं। देश के वर्तमान हालात के कारण यह जरूरी है कि गांधीजी, मौलाना मदनी और मौलाना आजाद के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए इस मुद्दे पर पुनः विचार किया जाए।"

टिप्पणी : हमारे पाठक क्योंकि जमीयत-ए-उलेमा नामक संगठन की पृष्ठभूमि को भलीभांति नहीं जानते इसलिए मौलाना नोमानी और उनके संगठन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना भी जरूरी है। यह संगठन वहाबी सम्प्रदाय की देवबंदी शाखा से संबंधित है। इसकी स्थापना 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान की गई थी। हालांकि इस देश में वहाबी सम्प्रदाय का एक लंबा और विवादित इतिहास है। इसी सम्प्रदाय से जुड़े हुए एक मुस्लिम धार्मिक और जिहादी नेता शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को भारत पर हमला करने का निमंत्रण दिया था। इस सम्प्रदाय का सबसे बड़ा संगठन दारूल उलूम देवबंद है, जिसकी विचारधारा से संबंधित अनेक जिहादी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पकड़े जा चुके हैं।

इंकलाब (3 जनवरी) के अनुसार आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत के हिंदुओं के देशभक्त होने के संदर्भ में दिए गए बयान पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आलोचना की है। ओवैसी ने कहा है कि क्या भागवत जवाब देंगे कि महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के बारे में उनका क्या कहना है? नेल्ली नरसंहार, 1984 के सिख विरोधी दंगे और 2002 के गुजरात दंगे के गुनाहगार कौन थे? ज्ञातव्य है कि डॉ. मोहन भागवत ने कहा था कि अगर कोई हिन्दू है तो वह निश्चित रूप से देशभक्त होगा। यह उनका मूल चरित्र और स्वभाव है। संघ प्रमुख ने महात्मा गांधी की उस टिप्पणी का हवाला देते हुए यह बात कही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि देशभक्ति की जड़ उनके धर्म में है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक धर्म को मानने वाले को अपने आप को देशभक्ति का प्रमाण पत्र क्यों जारी किया जा रहा है? जबकि दूसरों को अपना संपूर्ण जीवन यह सिद्ध करने में गुजारना पड़ता है कि उनको यहां रहने और स्वयं को हिन्दुस्तानी कहलाने का अधिकार है। जे.के. बजाज और एमडी श्रीनिवास की लिखी पुस्तक 'मेकिंग ऑफ ए हिन्दू पैट्रियट : बैकग्राउंड ऑफ गांधीजी हिंद स्वराज' का लोकार्पण करते हुए श्री मोहन भागवत ने कहा था कि पुस्तक के नाम और मेरे द्वारा उसके विमोचन से यह कहा जा सकता है कि यह गांधीजी को अपने दृष्टिकोण से पेश करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि महान हस्तियों को कोई अपने दृष्टिकोण से परिभाषित नहीं कर सकता। यह पुस्तक व्यापक शोध पर आधारित है और जिनको इससे मतभेद है वे भी इस संदर्भ में अनुसंधान करके लिखकर अपने दृष्टिकोण पेश कर सकते हैं। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि गांधीजी ने कहा था कि मेरी राष्ट्रभक्ति मेरे धर्म से निकलती है। मैं अपने धर्म को समझकर एक अच्छा राष्ट्रभक्त बनूंगा और लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहूंगा। ■

दिल्ली के कब्रिस्तानों में लूट पर रोक

इंकलाब (9 जनवरी) के अनुसार दिल्ली वक्फ बोर्ड ने यह निर्णय किया है कि भविष्य में राजधानी के कब्रिस्तानों के प्रबंधक शव दफनाने वालों से मनमानी रकम नहीं वसूल सकेंगे। बोर्ड ने यह तय किया है कि कब्र की खुदाई आदि पर जितना खर्च होता है उतनी ही धनराशि वसूल की जाएगी। फिलहाल बोर्ड ने एक शव को कब्र में दफनाने के लिए 3000 रुपये वसूल करने का फैसला किया है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान का कहना है कि 3000 रुपये में शव को दफन किया जा सकता है। मगर अभी तक कब्रिस्तानों के प्रबंधक जो लाखों रुपये इस संदर्भ में वसूल कर रहे थे उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त होगी तो कब्रिस्तान कमेटी के खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि उसे भंग भी कर दिया जाएगा। दिल्ली में वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार हालांकि 500 के लगभग कब्रिस्तान हैं लेकिन वे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। क्योंकि अधिकांश कब्रिस्तानों पर अनाधिकृत कब्जे करके वहां पर कॉलोनियों का निर्माण किया जा चुका है। अब दिल्ली में सिर्फ 25 कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनमें शवों को दफन किया जा सकता है। अधिकांश कब्रिस्तान माफिया गिरोहों के कब्जे में हैं जो कि शवों को दफन करने के लिए आने वाले लोगों से मनमाने रकम वसूल करते हैं। एक ही कब्रिस्तान में अलग-अलग मनमाने रेट हैं। अगर वहां किसी पीर की मजार है तो उसके समीप कब्र का अलग रेट है। इसी तरह से गेट के नजदीक और अंदर के दाम अलग-अलग हैं। हालत यह है कि कब्रिस्तानों में शवों को दफन करने के लिए अवैध रूप से लाखों रुपये वसूल किए जाते हैं। कुछ कब्रिस्तान ऐसे हैं जो कि 5 स्टार होटलों की तरह इतने महंगे हैं कि वहां पर कोई आम आदमी अपनी कब्र बनाने की सोच भी नहीं सकता है।

टिप्पणी : देश के विभाजन से पूर्व दिल्ली में मुसलमानों की जनसंख्या 5 लाख के लगभग थी जिसमें से लगभग तीन लाख पाकिस्तान चले गए। उस समय राजधानी में कब्रिस्तानों की संख्या 247 के लगभग थी। आजादी के बाद दिल्ली में मुसलमानों की आबादी में भारी वृद्धि हुई। इस समय दिल्ली में मुसलमानों की जनसंख्या 25-30 लाख के आसपास है। दिल्ली में जैसे ही भूमि की कीमतें बढ़ीं भूमाफियाओं ने कब्रिस्तानों पर अवैध कब्जे करके वहां पर कॉलोनियां बसा दीं। इस तरह से दिल्ली में बढ़ती हुई मुस्लिम जनसंख्या के लिए कब्रिस्तानों का संकट पैदा हुआ। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कब्रिस्तानों और वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे करवाने में वक्फ बोर्ड के भ्रष्ट कर्मचारियों का भी हाथ था। उन्होंने भूमाफियाओं के साथ गठजोड़ करके अनेक वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों से संबंधित दस्तावेज ही वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड से गायब कर दिए। इसके कारण से अधिकांश मामलों में वक्फ बोर्ड इन अवैध कब्जों के खिलाफ न्यायालयों में मुकदमें दायर करने की स्थिति में भी नहीं रहा। नगर में विस्तार के साथ-साथ अनेक बाहरी क्षेत्रों में मुसलमानों की बस्तियां बसीं मगर मुर्दों को दफनाने की समस्या दिन-प्रतिदिन जटिल होती गई। हालांकि इस्लाम के मुताबिक कब्रों को पक्का बनाना गैर-इस्लामिक हरकत माना जाता है। मगर इसके बावजूद दिल्ली के सभी कब्रिस्तानों में पक्की कब्रों की भरमार है। दिल्ली के मुसलमानों की मांग को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने नई बस्तियों के समीप 45 नए कब्रिस्तानों के लिए भूमि भी अलॉट की है। इनमें से मिलेनियम पार्क के समीप विकसित किया गया

कब्रिस्तान सबसे बड़ा है। राजधानी में मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या और कब्रों के लिए घटती हुई भूमि का लाभ कब्र माफियाओं ने उठाया। उन्होंने लाखों रुपये अवैध रूप से वसूलने के बाद शवों को दफनाने की अनुमति देने का नया सिलसिला शुरू किया जिस पर अब वक्फ बोर्ड ने लगाम लगाने का प्रयास किया है।

हिन्दू धर्म के अपमान पर मुस्लिम कॉमेडियन गिरफ्तार

इंकलाब (3 जनवरी) के अनुसार इंदौर मे एक शो में गृहमंत्री अमित शाह और हिन्दू देवी-देवताओं के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में हिंद रक्षक नामक संगठन ने मुंबई के एक कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की पहले पिटाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने फारूकी सहित पांच अन्य व्यक्तियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इस शो का आयोजन इंदौर में किया गया था। भाजपा की विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत पर मुनव्वर फारूकी को हिरासत में लिया गया है। फारूकी मूल रूप से गुजरात का रहने वाला है। एकलव्य सिंह गौड़ एक दर्शक के रूप में फारूकी के शो में गए थे। जब फारूकी ने हिन्दू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की तो उसपर एकलव्य सिंह ने आपत्ति की, जिस पर कार्यक्रम में जबर्दस्त हंगामा होने के कारण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। एकलव्य सिंह ने प्रमाण के रूप में एक वीडियो भी पुलिस को दिया है। उन्होंने संवाददाताओं को यह भी बताया कि फारूकी पहले भी अपने कार्यक्रमों में हिन्दू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता रहा है। इसलिए जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि फारूकी इंदौर के एक कैफे में कार्यक्रम कर रहा है तो वे टिकट लेकर अपने कुछ सहयोगियों के साथ वहां पहुंच गए और जब उन्होंने देखा कि गोधरा हत्याकांड में मरने वाले कारसेवकों के बारे में वह अभद्र टिप्पण कर रहा था तो उन्होंने इसका विरोध किया।

इंकलाब (5 जनवरी) के अनुसार मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी के चार दिन बाद उसके शो की एक महिला दर्शक ने यह दावा किया है कि फारूकी ने अपने शो में हिन्दू देवी-देवताओं का अपमान नहीं किया था। उसका कहना है कि पुलिस भी यह मान रही है कि एकलव्य सिंह ने जो वीडियो पुलिस के पास जमा करवाया था उसमें हिन्दू देवी-देवताओं के अपमान का कोई सबूत नहीं मिला है। नौकागंज पुलिस थाने के इंस्पेक्टर कमलेश शर्मा ने यह स्वीकार किया कि फारूकी के खिलाफ अभी तक पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। इस अधिकारी के अनुसार अभी तक फारूकी के खिलाफ देवी-देवताओं और गृह मंत्री अमित शाह के अपमान का कोई सबूत नहीं है। शिकायत करने वालों ने जो दो वीडियो पुलिस को दिए थे वे दूसरे कॉमेडियन के हैं जिसमें वे मुनव्वर फारूकी को गणेश से संबंधित एक लतीफा सुना रहे हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (5 जनवरी) ने लिखा है कि मुनव्वर फारूकी ने अपने कार्यक्रम में किसी हिन्दू देवी-देवता का अपमान नहीं किया और न ही गोधरा कांड से संबंधित ही कोई अपमानजनक बात कही है। समाचारपत्र ने इस बात की निंदा की है कि स्थानीय भाजपाई नेताओं के दबाव के कारण पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और इस संबंध में पांच लोगों को गिरफ्तार किया। समाचारपत्र ने इस संदर्भ में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है। समाचारपत्र ने यह मांग की है कि सरकार को साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को त्यागकर मुसलमानों के साथ न्यायोचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए और फारूकी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।

विश्व

बलूचिस्तान में सुन्नियों ने खेली शियाओं के खून की होली

रोजनामा सहारा (4 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में जिहादी आतंकवादी संगठनों ने शिया सम्प्रदाय के कम-से-कम 11 खदान मजदूरों का अपहरण करने के बाद उन्हें सामूहिक रूप से गोली से उड़ा दिया। स्थानीय पुलिस के अनुसार जब ये मजदूर खदान में काम करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें सशस्त्र आतंकवादियों ने घेर लिया और एक-एक मजदूर की पहचान करने के बाद उन्हीं की कमीजों से उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। इसके बाद उनके हाथों को पीछे बांध दिया गया। खास बात यह है कि जो मजदूर शिया नहीं थे उन्हें आतंकवादियों ने बिना कोई नुकसान पहुंचाए मौके पर ही छोड़ दिया। इसके बाद उग्रवादी इनको एक पहाड़ पर ले गए और वहां एक-एक करके गोली मार दी। इनमें से पांच की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि शेष अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस हत्याकांड की निंदा की है और इसे आतंकवादियों की एक अमानवीय हरकत बताया है। प्रधानमंत्री ने फ्रंटियर कोर को यह निर्देश दिया है कि वे इन हत्यारों को पकड़ने और उन्हें न्यायालय में पेश करने के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल करे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार मारे गए लोगों के परिवारजनों को हर तरह की सहायता प्रदान करेगी। पाकिस्तान स्थित ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त डॉ. ज्यॉफ्रे शॉ ने भी इस घटना की निंदा की है और उसे एक बुजदिल कार्रवाई बताया है।

सहाफत (6 जनवरी) के अनुसार अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि जिस भी गिरोह ने इन निर्दोष लोगों की हत्या की है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान का दुश्मन है। एक अन्य समाचार के अनुसार आईएसआईएस ने इस हत्याकांड की जिम्मेवारी ली है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि आईएसआईएस के जिस

गिरोह ने यह हत्या की है उसका मुख्यालय पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में। मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस्लामिक स्टेट के कई अड्डे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित हैं जिनके आतंकवादी काफी समय से इन क्षेत्रों में खून की होली खेल रहे हैं। मगर अभी तक उनको खत्म करने में पाकिस्तान सरकार और अफगानिस्तान सरकार दोनों ही विफल रही हैं।

इंकलाब (10 जनवरी) के अनुसार जिन शिया हज़ारा सम्प्रदाय के लोगों की आतंकवादियों ने हत्या की थी उनके परविारजनों ने उनके शव दफनाने से इनकार कर दिया था और सड़क पर उनकी लाशों को रखकर धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि प्रधानमंत्री इमरान खान मौके पर आएं और इस हत्याकांड के दोषियों को फौरन गिरफ्तार करवाएं। पाकिस्तान और बलूचिस्तान सरकार हज़ारा सम्प्रदाय के साथ कई दिन से समझौते की वार्ता कर रही थी। मगर मारे गए लोगों के परिवारजन अपना धरना खत्म करने और शवों को दफनाने के लिए तैयार नहीं थे। मगर बाद में बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री जाम कमल खान और पाकिस्तान के दो केन्द्रीय मंत्री अली जैदी और जुल्फी बुखारी और पाकिस्तान राष्ट्रीय असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी, जो कि एक सप्ताह से क्वेटा में डेरा डाले हुए थे, के प्रयास सफल हुए और एक सप्ताह बाद इनको क्वेटा के हज़ारा टाउन में स्थित कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इस अवसर पर हजारों व्यक्ति उपस्थित थे। इनमें पाकिस्तान के मंत्री अली जैदी, जुल्फी बुखारी, पाकिस्तान राष्ट्रीय असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी और बलूचिस्तान के गृहमंत्री मीर जिया उल्लाह लंगाउ सहित बलूचिस्तान के एक दर्जन मंत्री और विधायक शामिल थे। कासिम सूरी ने बताया कि इस बातचीत में शहीदों के परिवारजनों एवं हज़ारा बिरादरी द्वारा गठित शहीद कमेटी और शिया संगठन मजलिस वहादत उल मुस्लिमीन (एमडबल्यूएम) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पाकिस्तान सरकार ने मृतकों के परिवारजनों की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है और इस बात का आश्वासन दिया है कि शवों को दफनाने के तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान घटनास्थल पर आएंगे और मृतकों के परिवारजनों से मुलाकात करेंगे। ज्ञातव्य है कि बातचीत में इस बात से भी गतिरोध पैदा हो गया था जब इमरान खान ने अपने ट्विटर में यह आरोप लगाया था कि परिवारजन शवों को दफन न करके सरकार को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं। बाद में इमरान खान ने अपने इस ट्विट पर खेद व्यक्त किया और कहा कि उनका इशारा विपक्षी दलों की ओर था और उन्होंने इस संदर्भ में पीडीएम के नेताओं का उल्लेख किया था।

शवों को दफनाने के दूसरे दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान क्वेटा पहुंचे और उन्होंने मछ में परिवारजनों के घर जाकर संवेदना व्यक्त की और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि भविष्य में शिया हज़ारा बिरादरी को पाकिस्तान सरकार द्वारा संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि आगे कोई ऐसी घटना न हो। उन्होंने यह कहा कि गत 22 वर्ष से आतंकवादी इस बिरादरी को अपना निशाना बना रहे हैं मगर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार कोई भी ठोस कार्रवाई करने में आज तक विफल रही है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद शिया हज़ारा बिरादरी के नेता आगा रजा ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि

प्रधानमंत्री ने मारे गए व्यक्तियों के परिवारजनों को 25-25 लाख रुपये मुआवजा तुरंत देने का आश्वासन दिया है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में सुरक्षा के लिए सेना की विशेष चौकियां स्थापित की जा रही हैं। समाचारपत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा लगातार हालात पर नजर रख रहे हैं और वे शीघ्र ही बलुचिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ताकि इस क्षेत्र में सुरक्षा की व्यवस्था को और कड़ा बनाया जा सके।

लखनऊ से प्रकाशित समाचारपत्र **अवधनामा** ने 7 जनवरी के अंक में मुख्य पृष्ठ पर एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें लिखा है कि बलूचिस्तान के मछ क्षेत्र में 11 खदान मजदूरों के कत्ल के खिलाफ पाकिस्तान में विरोधी धरनों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस्लामाबाद में इस धरने का नेतृत्व एमडबल्यूएम के प्रमुख राजा नासिर अब्बास जाफरी ने की। बाद में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो पूरे पाकिस्तान में सड़कों को जाम कर दिया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री इमरान खान से मांग की कि वे मौके पर जाएं और इंसाफ दें। उन्होंने इस बात पर हैरानी प्रकट की कि एक वर्ष के बाद पाकिस्तान में आतंकवाद फिर से सिर उठाने लगा है। आखिर हमलोग कब तक मरते रहेंगेघ उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका इस्लामिक स्टेट की जड़ें अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जमा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि इमरान खान को कुछ लोग क्वेटा जाने से रोक रहे हैं। ऐसे लोग पाकिस्तान के वफादार नहीं हैं। पाकिस्तान सबका साझा है जिसकी नींव इस्लाम पर रखी गई है। यह किसी एक सम्प्रदाय की जागीर नहीं है। कराची में भी 12 स्थानों पर धरने दिए गए। फैसलाबाद डिविजन में 19 स्थानों पर धरने दिए गए। धरनों में भाग लेने वाले शियाओं के हत्यारों के खात्मे की मांग कर रहे थे।

समाचारपत्र ने कहा है कि शिया संगठन ने 7 मांगें सरकार के सामने रखी हैं जिनमें इस घटना के दोषियों की गिरफ्तारी और आतंकवादियों के राष्ट्रीय नेटवर्क के सफाए के लिए देशव्यापी सैनिक अभियान फौरन शुरू करने और पूरे पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करने की मांग है। इसके अतिरिक्त यह भी मांग है कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारजनों को कम-से-कम 50-50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। इस घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित किया जाए और बलूचिस्तान के शिक्षा संस्थानों और बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था सेना के हवाले की जाए। इसके अतिरिक्त इस बात पर भी जोर दिया गया है कि क्योंकि बलूचिस्तान सरकार शियाओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है इसलिए बलुचिस्तान के संपूर्ण मंत्रिमंडल को तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। पाकिस्तान के गृहमंत्री शेख रशीद अहमद ने यह स्वीकार किया कि इस हत्याकांड के पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ होने की पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि अभी तक इस संबंध में कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री जाम कमल खान को यह निर्देश दिया है कि वे दुबई के अपने दौरे को रद्द करके फौरन क्वेटा पहुंचें ताकि आतंकवादियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान सेना द्वारा शुरू किया जा सके।

शियाओं का कत्लेआम

पाकिस्तान का गठन एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में किया गया था। इसलिए सबसे पहले वहां पर हिंदुओं को चुन-चुनकर निशाना बनाया गया। देश के विभाजन के समय इस क्षेत्र में हिन्दू आबादी 45 प्रतिशत थी जो कि अब घटकर डेढ़ प्रतिशत ही रह गई है। पाकिस्तान में बचे-खुचे हिंदुओं का उत्पीड़न और उनका जबरन धर्मांतरण वहां रोजमर्रा की घटना बन चुका है। हिन्दू लड़कियों का सरेआम अपहरण करके उनका मुसलमानों के साथ जबरन निकाह कराया जाता है। हिंदुओं के बाद ईसाईयों को भी कट्टरपंथियों ने अपना निशाना बनाया और पाकिस्तान के कुख्यात ईशनिंदा कानून के तहत अनेक ईसाईयों को मस्जिदों के इमामों की न्यायालयों में झूठी गवाहियों के आधार पर मौत की सजा दी गई। खास बात यह है कि पाकिस्तान के निर्माण में जिन अहमदियों और शियाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया था वे भी सुन्नी आतंकियों के उत्पीड़न से बच नहीं पाए। 1960 के दशक में दो लाख अहमदियों का कत्लेआम किया गया। उनके चौथे खलीफा को जान बचाकर लंदन भागना पड़ा और अभी तक वे लंदन में ही निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कट्टरपंथी मुल्लाओं के दबाव पर पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने भुट्टो के शासनकाल में अहमदियों को गैर-मुस्लिम घोषित कर दिया।

जहां तक शियाओं का संबंध है पाकिस्तान के तानाशाह जिया उल हक ने देश के इस्लामीकरण का जो अभियान छेड़ा था उसके बाद पाकिस्तान में शियाओं का जीना दूभर हो गया। वहाबी मुसलमानों ने अपना एक आतंकवादी संगठन सिपाह-ए-सहाबा पाकिस्तान (एसएसपी) का गठन किया। बाद में नेतृत्व के प्रश्न पर इसमें विभाजन हुआ और एक ग्रुप लश्कर-ए-झंग्वी (एलईजे) के नाम से इससे अलग हो गया। सुन्नियों का एक और जिहादी संगठन अहले सुन्नत वल जमात (एएसडबल्यूजे) है। इन संगठनों की ओर से शियाओं के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 5000 से अधिक शिया मारे जा चुके हैं। हाल ही में एलईजे ने शिया हज़ारा सम्प्रदाय के खिलाफ एक फतवा जारी किया था जिसमें उन्हें वाजिब-उल-कत्ल (धर्म के अनुसार हत्या किए जाने के योग्य) कहा गया था। इसके जवाब में शिया भी अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाने पर विवश हुए और उन्होंने अपना एक आतंकवादी संगठन मजलिस वहादत-ए-मुस्लिमीन (एमडबल्यूएम) बनाया। अब यह जिहादी संगठन पंजाब, सिंध, खैबर पख़्तूनख़्वा, बलूचिस्तान, गिलगित और पाक अधिकृत कश्मीर में अपना पैर पसार चुका है। इस संगठन की ओर से विश्वभर में पाकिस्तान में शिया बिरादरी के उत्पीड़न के मामले को उठाया जाता है।

कौन हैं शिया हज़ारा सम्प्रदाय?

जहां तक हज़ारा सम्प्रदाय का संबंध है ये मूलत: मंगोल नस्ल के हैं और शिया विचारधारा में विश्वास रखते हैं। इनके संबंध में बाबर ने 'बाबरनामा' में उल्लेख किया है और इन्हें हज़ारात शिया कबीला का नाम दिया है। इससे पहले इब्न-बतुता ने भी तुगलक वंश के समय में इस कबीले का उल्लेख करते हुए इन्हें सुल्तान मोहम्मद तुगलक के सेनापतियों में शामिल बताया है। इनकी संख्या का अनुमान 15 से 20 लाख के बीच लगाया जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत में इनके एक सरदार अब्दुल खालिक हज़ारा ने अफगानिस्तान के शाह नादिर शाह की हत्या 1933

में कर दी थी। इस घटना के बाद अफगानिस्तान में इस कबीले का उत्पीड़न शुरू हो गया और लगभग दो लाख हज़ारा अफगान सैनिकों के द्वारा मार दिए गए। इस हत्याकांड के बाद पांच से सात लाख हज़ारा अफगानिस्तान से अपनी जान बचाकर बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और दुबई भाग गए।

1983 में जनरल जियाउल हक के इशारे पर सुन्नी जिहादी संगठनों ने शियाओं के खिलाफ खूनी जिहाद शुरू किया, जिसके कारण कराची, हैदराबाद स्वात, चित्राल और गिलगित में हजारों शियाओं को सुन्नी आतंकी संगठनों ने मौत के घाट उतार दिया। इन सुन्नी आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान सरकार का समर्थन प्राप्त था। हज़ारा कबीला के शियाओं के प्रमुख हत्याकांडों का विवरण इस प्रकार है।

- 2003 में क्वेटा में इनकी मस्जिद में सुन्नी संगठनों ने बम फेंके जिसके कारण वहां पर 47 नमाजी मौके पर मारे गए।
- 2004 में इनके एक जुलूस पर अंधाधुंध गोली चलाई गई जिसके कारण 42 हज़ारा शियाओं की हत्या की गई।
- 2010 में क्वेटा के एक अस्पताल में भर्ती आठ हज़ारा रोगियों को आतंकवादियों ने गोली से उड़ा दिया।
- 2012 में जब हज़ारा कबीले की महिलाएं और बच्चे एक वैन में सवार होकर सिबी से पिशीन जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें घेरकर गोलियों से भून दिया गसर जिसमें सात महिलाएं और पांच बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई।
- 2013 में बलूचिस्तान में अनेक जगहों पर बम फटे जिसमें 52 हज़ारा शिया मारे गए।

2018 में पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें इस बात को स्वीकार किया गया कि गत 14 वर्षों में 5000 से अधिक हज़ारा शिया हिंसक घटनाओं में मारे गए हैं। अक्टूबर 2016 में एक बस को रोककर सुन्नी आतंकवादियों ने चुन-चुनकर 7 पुरुषों और 4 महिलाओं को गोली से उड़ा दिया। सितंबर 2017 में एक मस्जिद में घुसकर वहां नमाज पढ़ रहे चार नमाजियों की हत्या की गई। अप्रैल 2019 में क्वेटा की हज़ारा हाउसिंग सोसायटी के साप्ताहिक बाजार में एक आत्मघाती जिहादी ने 21 व्यक्तियों की हत्या कर दी। इस हत्याकांड की जिम्मेवारी इस्लामिक स्टेट ने ली।

बाली बम धमाकों का मास्टरमाइंड रिहा

इंकलाब (9 जनवरी) के अनुसार इंडोनेशिया के अतिवादी इस्लामिक धार्मिक नेता अबु बकर बशीर को जेल से रिहा कर दिया गया है। इस पर 2002 में बाली में हुए बम धमाके का मास्टरमाइंड होने का आरोप था। बताया जाता है कि वह आतंकवादी इस्लामिक संगठन जेमाह इस्लामिया का प्रमुख है, जिसका संबंध अलकायदा से था। 82 वर्षीय अबु बकर को दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया का सबसे महत्त्वपूर्ण अतिवादी इस्लामिक नेता माना जाता है। ज्ञातव्य है कि अक्टूबर 2002 में होने वाले धमाकों की शृंखला की साजिश थाइलैंड के एक होटल में रची गई थी। इस गुप्त बैठक में दक्षिणी एशिया में सक्रिय जिहादी संगठन जेमाह

इस्लामिया के नेताओं ने भाग लिया था, जिसमें यह तय किया गया था कि नाइट क्लबों, शराबखानों और विदेशी दूतावासों को निशाना बनाया जाए। इस बम कांड के एक आरोपी ने यह स्वीकार किया था कि बाली में बम धमाके करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि वहां की अधिकांश आबादी हिन्दू है और वहां पर इसके अतिरिक्त काफी गैर-मुस्लिम पर्यटक भी आते हैं। एक अन्य आरोपी अली इमरोन के अनुसार मध्य जावा के सोलो में एक गुप्त बैठक हुई थी, जिसको संबोधित करते हुए इमाम समुद्रा ने कहा था कि उनकी यह कार्रवाई विश्वव्यापी इस्लामिक जिहाद का हिस्सा है और इसका उद्देश्य अफगानिस्तान के मुसलमानों को अमेरीकियों के उत्पीड़न से बचाना है।

बताया जाता है कि इस संगठन के प्रमुख हंबली उर्फ इस्लामुद्दीन का संपर्क अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन से था। हंबली अभी तक अमेरिका के एक कैदखाने में है। बाली में बम विस्फोट की योजना 43 वर्षीय इस्लामिक मदरसे के अध्यापक अली गुफरान ने तैयार की थी। ज्ञातव्य है कि इन धमाकों में 202 व्यक्ति मारे गए थे जिनमें 88 विदेशी थे। इंडोनेशिया के इतिहास में यह सबसे खतरनाक आतंकवादी हमला था। इस हमले की जांच के दौरान इदरिस नामक एक अन्य व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अली इमरोन से बमों को प्राप्त करके उन्हें बाली पहुंचाया था। अमरोजी नामक एक अन्य अभियुक्त ने यह स्वीकार किया था कि उसने सारी क्लब में हुए बम धमाके के बम को बनाने के लिए कैमिकल का इस्तेमाल किया था। उसने उन आरोपियों का नाम भी बताया था जिन्होंने इन बमों को तैयार किया था। इनमें अब्दुल गनी, उमर पातेक आदि शामिल थे। अली इमरोन बमों को एक वैन में भरकर इस क्लब में ले गया था। इस वैन के चालक जिमी ने इस वैन में पहले स्वयं को एक बम धमाके से उड़ाया जिसके बाद इस वैन में रखे सभी बम फट गए।

इसी तरह इकबाल नामक एक अन्य व्यक्ति ने भी आत्मघाती फिदाइन की भूमिका निभाते हुए खुद को एक अन्य क्लब में बम से उड़ा लिया था। जबकि दो बम मौके पर पहुंचने से पहले रास्ते में ही फट गए, जिससे उन्हें ले जाने वाले तीन आदमी मारे गए। इस मुकदमें में चार व्यक्तियों को मौत की सजा दी गई थी। जबकि अन्य संदिग्ध आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। इनमें अल जाहिरी हुसैन भी शामिल था जिसे जेमाह इस्लामिया संगठन में बम बनाने का विशेषज्ञ माना जाता था उसे पुलिस ने 2005 में पूर्वी इंडोनेशिया में हुई एक मुठभेड़ में मार गिराया था। जबकि बम बनाने का एक अन्य एक्सपर्ट नूरूद्दीन मोहम्मद पुलिस द्वारा मारे गए एक छापे के दौरान हुए धमाके में 2009 में मारा गया था। दुलमतीन नामक एक अन्य आतंकवादी को पुलिस ने उस वक्त मार गिराया जब वह मार्च 2010 में एक इंटरनेट कैफे में विस्फोट करने का प्रयास कर रहा था। इन सारे आतंकी गिरोह का असली प्रेरक 82 वर्षीय अबु बकर अल बशीर था जिसे न्यायालय ने उम्रकैद की सजा दी थी। मगर

अपील करने पर उच्च न्यायालय ने उसको दोषमुक्त कर दिया था। लेकिन उसके खिलाफ यह भी आरोप था कि उसने आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने के लिए अनेक गुप्त प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के लिए आर्थिक सहायता दी थी। इसलिए अभी तक वह जेल में ही था।

इंडोनेशिया सरकार के एक प्रवक्ता ने अबु बकर बशीर को जेल से रिहा करने की घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस जिहादी को इसलिए रिहा किया गया है ताकि वह इंडोनेशिया के मुसलमानों में जिहाद के खिलाफ जागृति पैदा कर सके। ताकि भविष्य में इंडोनेशिया के मुसलमान जिहादी हिंसा से दूर रहें। प्रवक्ता ने यह स्वीकार किया कि अबु बकर बशीर के वकील ने इस बात की मांग की थी कि इंडोनेशिया में व्यापक कोरोना महामारी को देखते हुए इस इस्लामिक धार्मिक नेता को जेल से रिहा किया जाए। इंडोनेशिया की सरकार ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार करके इस 82 वर्षीय जिहादी को रिहा करने का फैसला किया है।

समाचारपत्रों के अनुसार जब एक आतंकवादी अमरोजी को न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई तो उसने हंसते हुए कहा कि उसे इस्लाम के लिए शहीद होने पर गर्व है।

अफगान फौजियों पर हमले में चीन का हाथ

सियासत (2 जनवरी) के अनुसार अमेरिकी सूत्रों ने चीन पर यह आरोप लगाया है कि वह अफगानिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए धनराशि बांट रहा है। चीन सरकार ने इस आरोप का खंडन किया है और कहा है कि अमेरिका का लक्ष्य सिर्फ चीन को बदनाम करना है। चीन किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। अमेरिका क्योंकि अफगानिस्तान में अभी तक शांति स्थापित करने में विफल रहा है और वहां पर तालिबान और इस्लामिक स्टेट सरकारी फौजियों और नागरिकों के खून की होली खेल रहे हैं इसलिए अमेरिका अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए चीन को दोषी ठहरा रहा है। एक अमेरिकी प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि हाल ही में अफगानिस्तान में जो हिंसक घटनाओं में तेजी आई है उसके पीछे चीन और उसके कुछ विदेशी समर्थकों का हाथ है जो यह नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो।

अफगानिस्तान में बम वर्षा से एक ही परिवार के 18 लोग मरे

इंकलाब (12 जनवरी) के अनुसार अफगानिस्तान के सूबा कंधार में एक घर पर अफगान वायुसेना ने बम बरसाए जिसके कारण कम-से-कम 18 व्यक्ति मारे गए। मरने वालों में 8 बच्चे, 7 महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं। गांव वालों ने सड़क पर इन लाशों को रखकर धरना देना शुरू कर दिया है और वे सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि वे दोषी विमान चालकों के खिलाफ कार्रवाई करें। गजनी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य मोहम्मद नासिर ने कहा है कि बम वर्षा में मारे जाने वाले लोग आतंकवादी नहीं बल्कि निर्दोष नागरिक थे इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि

वह न्याय दे। दूसरी ओर सरकार ने यह दावा किया है कि गुप्तचर सूत्रों की सूचनाओं के आधार पर तालिबान के एक अड्डे पर बमबारी की गई थी जिसमें तालिबान मारे गए हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ नागरिक भी हों जो वहां छिपे हुए थे। हालांकि तालिबान और सरकार के बीच समझौता वार्ता चल रही है मगर इसके साथ-साथ ही दोनों ओर से हिंसक गतिविधियां भी जारी हैं।

सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले मैसेज शेयर करने पर मृत्युदंड

इंकलाब (9 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तान में आतंकवाद निरोधक एक अदालत ने सोशल मीडिया पर समाज के विभिन्न वर्गों में वैमनस्य पैदा करने वाली सामग्री को शेयर करने के आरोप में तीन लोगों को फांसी की सजा सुनाई है जबकि चौथे आरोपी को दस वर्ष की कड़ी सजा दी गई है। फरार चार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए देशव्यापी वारंट जारी कर दिए गए हैं। इस केस की जांच करने वाले संस्थान संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के अनुसार राणा नोमान रफाकत और अब्दुल वाहिद जाली पेज चलाते थे और सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री का प्रसार करते थे जिससे पाकिस्तान के विभिन्न वर्गों के बीच नफरत और हिंसा की भावना पैदा होती थी। जबकि नासिर अहमद यूट्यूब पर यह सामग्री अपलोड करता था। पाकिस्तान का गुप्तचर विभाग इन दिनों सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखे हुए है। वह काफी समय से इस गिरोह का सुराग लगाने का प्रयास कर रही थी। 19 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान की फेडरल जांच एजेंसी इस गिरोह का सुराग लगाने में सफल हुई।

एफआईआर के अनुसार बहुत से अज्ञात लोग इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट वगैरह का इस्तेमाल करते हुए फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और वेबसाइट के द्वारा विभिन्न वर्गों के बीच नफरत और हिंसा फैलाने वाली सामग्री का प्रसारण कर रहे थे और इस्लाम से संबंधित विभिन्न पवित्र हस्तियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी, ग्राफिक डिजाइंस, फोटो, ड्रॉइंग और वीडियो का इस्तेमाल करके जानबूझकर विभिन्न वर्गों के धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे और उन्हें हिंसा के लिए उत्तेजित कर रहे थे। एफआईआर के अनुसार चौथा आरोपी प्रो. अनवर अहमद को दस वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आरोपी एक कॉलेज में उर्दू का प्रोफेसर था। उसे इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज में भाषण के दौरान इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक भावनाओं को फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन चारों लोगों को पैगम्बर की तौहीन के एक्ट के तहत प्रारम्भिक तौर पर गिरफ्तार किया गया था। इन चारों आरोपियों ने उन पर लगाए गए आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मगर न्यायालय में पेश किए गए सबूतों के आधार पर न्यायालय ने इनके खिलाफ फर्ज जुर्म 2017 को लगा दिया था। अब न्यायालय ने इनमें से तीन को मौत की सजा और एक को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। क्योंकि उन्हें आतंकवाद निरोधक न्यायालय ने यह सजा दी है इसलिए वे इसके खिलाफ किसी उच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकते।

पश्चिम एशिया

सऊदी अरब और कतर के संबंधों में सुधार से अरब जगत में नई शुरुआत

इत्तेमाद (6 जनवरी) के अनुसार सऊदी अरब एवं उसके सहयोगी देशों और कतर के बीच मतभेद समाप्त होने से अरब जगत की राजनीति में नई शुरुआत हुई है। पर्दे के पीछे जो प्रयास चल रहे थे उसके परिणामस्वरूप कतर के अमीर शेख तमीम बिन हामद अल थानी ने खाड़ी देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अचानक सऊदी अरब का दौरा किया। उनके वहां पर पहुंचते ही सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों ने कतर की नाकाबंदी समाप्त करने की घोषणा कर दी। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने कतर के शासक शेख तमीम बिन हामद अल थानी का स्वागत किया।

ज्ञातव्य है कि 2017 में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और बहरीन ने कतर पर यह आरोप लगाया था कि वह आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने उसकी नाकेबंदी कर दी थी। हालांकि कतर ने इन आरोपों का हमेशा खंडन किया। बताया जाता है कि सऊदी अरब और कतर के बीच सुलह करवाने में अमेरिका और कुवैत का प्रमुख हाथ रहा है। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सऊदी अरब के युवराज ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र के विकास के लिए यह जरूरी है कि खाड़ी देशों के संबंधों में सुधार हो ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से उत्पन्न होने वाले खतरे का मुकाबला किया जा सके। खाड़ी देशों के छह प्रमुखों ने दो दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए। खाड़ी देशों की राजनीति में आए इस नए मोड़ के कारण एशिया के स्टॉक मार्केट में भारी उछाल आया है। खाड़ी

देशों में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और कतर शामिल हैं। बताया जाता है कि अमेरिका को कतर के ईरान के साथ बढ़ते हुए संबंधों के बारे में परेशानी थी इसलिए उसने कतर की नाकेबंदी करवाने में विशेष रुचि ली थी।

इंकलाब (12 जनवरी) के अनुसार चार वर्ष के बाद सऊदी अरब और कतर के बीच विमान सेवा शुरू हो गई है। कतर एयरवेज ने रियाद, जेद्दा और दम्माम के बीच विमान चलाने की घोषणा की है। एयरलाइंस ने कहा है कि हम सऊदी अरब में अपने व्यापारी और कारोबारी सहयोगियों के साथ मजबूत संबंध चाहते हैं। एक अन्य घोषणा के अनुसार सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बाद अब बहरीन ने भी कतर के साथ यात्रा संबंध बहाल करने की घोषणा की है। बहरीन ने भी चार वर्ष के बाद कतर के साथ विमान संबंध शुरू किए हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बाद बहरीन कतर के साथ समुद्री और वायु रास्ते खोलने वाला तीसरा अरब देश बन गया है। 2017 में सऊदी अरब सहित छह अरब देशों ने कतर पर यह आरोप लगाया था कि वह आतंकवाद की ज्वाला को भड़का रहा है और उसके साथ अपने डिप्लोमैटिक, व्यापारिक और आवागमन के साधन तोड़ लिए थे। इस महीने के शुरुआत में खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के अधिवेशन में भाग लेते हुए सऊदी अरब ने कतर के साथ अपने संबंध पुनः स्थापित करने की घोषणा की थी। बताया जाता है कि इस राजनीतिक मोड़ के पीछे अमेरिका का हाथ है।

इत्तेमाद (7 जनवरी) के अनुसार सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने घोषणा की कि कतर के साथ सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र के अच्छे संबंध स्थापित हो गए हैं और सभी शिकायतें दूर हो गई हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इन विवादों को दूर करने में कुवैत की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। इन सभी देशों ने यह तय किया है कि वे भविष्य में किसी भी तरह के आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। अल-उला संधि के अनुसार इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाला कोई भी देश एक दूसरे के प्रति कोई आतंकवादी कार्रवाई नहीं करेगा। किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए सभी देश एक दूसरे को पूर्ण सहयोग देंगे।

सियासत (7 जनवरी) ने अपने संपादकीय में खाड़ी सहयोग परिषद के शिखर सम्मेलन में हुए निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि इससे अरब जगत में नई शुरुआत होगी और आपसी एकता, खुशहाली और नई ताकत के रास्ते खुलेंगे। समाचारपत्र ने इस बात की आलोचना की है कि अल-उला समझौते में जिस तरह से ईरान का उल्लेख किया गया है वह मुस्लिम एकता के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। समाचारपत्र ने यह भी कहा है कि इजरायल का इन देशों में प्रभाव बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इन देशों का रूख इजरायल के प्रति मैत्रीपूर्ण हुआ है। इस परिवर्तन का क्या लाभ होगा अभी इसका अनुमान लगाना सही नहीं है। समाचारपत्र ने यह इशारा किया है कि अमेरिका हो या इजरायल उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि हैं। ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल की नीति किसी से छिपी हुई नहीं है।

सियासत ने 12 जनवरी के अंक में कतर और सऊदी अरब की कारोबारी दोस्ती पर संतोष प्रकट करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच

संबंधों में जो सुधार हुआ है वह पूरे इस्लामिक जगत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुस्लिम देशों को पश्चिमी देशों पर इस बात के लिए दबाव डालना चाहिए कि वे फिलिस्तीन के लिए अलग स्वशासी राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दें। इजरायल ने जबरन जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है उनको खाली करवाना बेहद जरूरी है।

अखबार-ए-मशरिक (कोलकाता) ने 13 जनवरी के संपादकीय में कतर और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। हालांकि समाचारपत्र ने यह शिकायत की है कि भारत की राष्ट्रीय मीडिया ने इसे खास महत्व नहीं दिया। समाचारपत्र ने शिकायत की है कि खाड़ी के देशों में अमेरिका का जिस तरह से प्रभाव बढ़ रहा है उसे मुसलमानों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समाचारपत्र ने यह आशा व्यक्त की है कि सऊदी अरब और कतर मिलकर खाड़ी देशों के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देंगे। इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के मुसलमानों की निगाहें खाड़ी क्षेत्र में हुए इस परिवर्तन की ओर लगी हुई हैं।

सऊदी अरब में पहली बार संगीत और अभिनय के लिए लाइसेंस

इंकलाब (1 जनवरी) के अनुसार इस्लामिक जगत के महत्त्वपूर्ण देश सऊदी अरब में इतिहास में पहली बार संगीत, अभिनय, फैशन, साहित्य आदि विषयों में प्रशिक्षण के लिए दो संस्थानों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। गत कई शताब्दी से सऊदी अरब में संगीत, अभिनय और कला के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध था। पांच वर्ष पूर्व सऊदी सरकार ने इस बात की अनुमति दी थी कि देश में संगीत, अभिनय और फैशन से संबंधित कार्यक्रमों का सार्वजनिक रूप से आयोजन किया जा सकता है। मगर इस बात पर प्रतिबंध था कि किसी कार्यक्रम में महिलाएं और पुरुष संयुक्त रूप से भाग नहीं ले सकते। हाल ही में महिलाओं को पुरुषों के साथ काम करने की भी अनुमति दी गई है।

सरकारी अखबार 'सऊदी गजट' के अनुसार अरब के संस्कृति मंत्री ने इस बात की पुष्टि की

है कि सऊदी सरकार ने 'द इंटरनेशनल म्युजिक ट्रेनिंग सेंटर' और 'म्युजिक हाउस फॉर ट्रेनिंग ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट' को विधिवत लाइसेंस जारी किए गए हैं। सांस्कृतिक विभाग के मंत्री शहजादा बदर बिन अब्दुल्ला ने कहा है कि जो व्यक्ति इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेना चाहे उन्हें इस बात की अनुमति है। इन दोनों संस्थानों को तीन महीने के भीतर कार्य शुरू करना होगा और उनके कार्यक्रम में महिलाओं और पुरुष दोनों को प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति होगी।

अमेरिका द्वारा हूती संगठन को आतंकवादी संगठन का दर्जा

इंकलाब (12 जनवरी) के अनुसार अमेरिका ने यमन में सक्रिय हूती संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प मध्य पूर्व में अपने घोषित एजेंडे को इस तरह से पूरा करना चाहते हैं। ट्रम्प के प्रयास से चार मुस्लिम देश इजरायल को मान्यता दे चुके हैं और इस क्षेत्र से ईरान के प्रभाव को कम करने में भी अमेरिका को सफलता मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रयास से सऊदी अरब और अन्य अरब देशों ने कतर के साथ तीन वर्ष बाद संबंध स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। ज्ञातव्य है कि हूती यमन से सऊदी अरब के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। कहा जाता है कि हूतियों को ईरान का पूरा समर्थन प्राप्त है और उन्हें ईरान द्वारा बराबर अस्त्र-शस्त्र सप्लाई की जाती है।

विमान दुर्घटना में मरने वालों को ईरान मुआवजा देगा

इंकलाब (1 जनवरी) के अनुसार ईरान सरकार ने गत वर्ष के जनवरी महीने में यूक्रेन की विमान दुर्घटना में मरने वाले 176 यात्रियों के परिवारजनों को डेढ़-डेढ़ लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। ज्ञातव्य है कि ईरान के सैनिक अड्डे से गलती से चले एक मिसाइल ने इस विमान को तबाह कर दिया था। ईरान के संचार मंत्री ने ईरानी संवाद एजेंसी को बताया कि इस दुर्घटना से संबंधित रिपोर्ट उन सभी देशों को भेज दी गई है जो कि इस जांच में शामिल थे।

ज्ञातव्य है कि अमेरिका द्वारा पासदारान-ए-इंकलाब के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने इराक में मार गिराया था जिसके बाद 9 जनवरी को ईरान की सेना ने यूक्रेन

इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक यात्री विमान को अपने मिसाइल का निशाना बनाया था, जिसमें 167 यात्री मारे गए थे। ईरान सरकार ने यह स्वीकार किया है कि उसकी सेना की गलती के कारण यह हुआ था इसलिए वह दोषी है। इस घटना के बाद ईरान और अमेरिका के संबंधों में बहुत अधिक कटुता बढ़ गई थी। बताया जाता है कि जब तेहरान के इमाम खोमैनी हवाई अड्डा से यह यूक्रेनी विमान उड़ान भर रहा था तो वह ईरानी मिसाइल का निशाना बन गया। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 176 बताई थी, जिनमें 167 यात्री और शेष विमान के चालक और उनके सहयोगी आदि शामिल थे। मरने वालों में 82 ईरानी, 63 कनाडाई, 4 अफगान, दो जर्मन और 3 ब्रिटिश नागरिक शामिल थे। जबकि यूक्रेनी नागरिकों की संख्या 11 थी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने यह स्वीकार किया है कि ईरानी सेना की गलती से यह दुर्घटना हुई। इसलिए ईरान को उस पर खेद है।

जनरल सुलेमानी की पहली बरसी

इंकलाब (4 जनवरी) के अनुसार ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और अबु महदी की पहली बरसी के अवसर पर बगदाद के तहरीर स्क्वायर में लाखों इराकी नागरिकों ने शहीद सुलेमानी और उनके साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इराक के साथ-साथ ईरान, सीरिया, लेबनॉन, यमन और अन्य देशों में सुलेमानी की बरसी मनाई गई। प्रदर्शनकारियों ने सुलेमानी और अन्य शहीदों के चित्रों के साथ-साथ इराकी जिहादी संगठन पीएमएफ के झंडे भी उठा रखे थे। प्रदर्शनकारी इराक से अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन की मांग करने के साथ-साथ हत्यारों के खिलाफ बदले की कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे थे। तेहरान में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए ईरान के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख इब्राहिम रईसी और पासदारान-ए-इंकलाब के प्रमुख मेजर जनरल हसन सलामी ने कहा कि तेहरान ने अभी तक सुलेमानी की मौत का बदला नहीं लिया। यह बदला जरूर लिया जाएगा और उनके हत्यारों को चाहे वे किसी

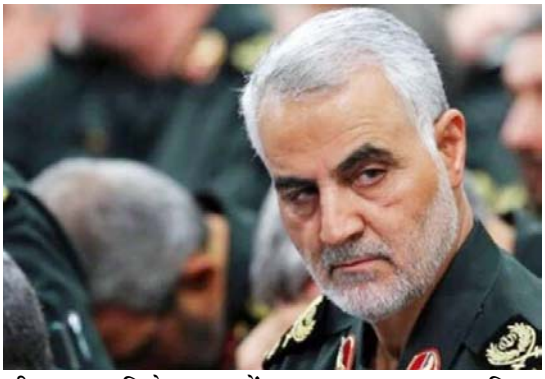

भी जगह छिपे हुए हों चुन-चुनकर खत्म किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने काले कपड़े पहन रखे थे।

बगदाद में एक अन्य स्थान पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए अल फतह इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख हादी अल-अमीरी ने संबोधित करते हुए कहा कि हम शहीदों के रास्ते पर हमेशा चलते रहेंगे। मुसलमानों के उत्पीड़न को हर कीमत पर रोका जाएगा और सुलेमानी और उनके सहयोगियों के कातिलों का बदला लिया जाएगा।

अलकायदा का नया अड्डा ईरान

इंकलाब (14 जनवरी) के अनुसार अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यह आरोप लगाया है कि अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक आतंकवादी संगठन का नया अड्डा ईरान में बनाया गया है। हालांकि उन्होंने इस आरोप का कोई प्रमाण पेश नहीं किया। ईरान ने अमेरिका के इस आरोप को निराधार और मनगढ़ंत बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अलकायदा ने तेहरान में अपना अड्डा बना लिया है और वहां पर अपनी लीडरशीप को नया रूप दे दिया है। अलकायदा के प्रमुख के सहायक वहां पर मौजूद हैं और वे वहां पर नए अफगानिस्तान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे स्थिति और भी खराब होगी। क्योंकि अभी तक अलकायदा का मुख्यालय अफगानिस्तान की पहाड़ियों में था और उन्हें अफगानी सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं था। मगर अब ईरान सरकार उन्हें हर तरह का समर्थन दे रही है।

ज्ञातव्य है कि माइक पोम्पियो के दिन अब गिने चुने हैं। क्योंकि पुराने राष्ट्रपति की कार्यावधि समाप्त होते ही नया विदेश मंत्री कार्यभार संभालेगा। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि हम अलकायदा और इस्लामिक स्टेट का निशाना रहे हैं और हमने उनका डटकर मुकाबला किया है और उनकी हिंसा का हम शिकार भी बने हैं। इसलिए अमेरिका का यह खतरनाक झूठ है। जवाद जरीफ ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ फर्जी आरोप गढ़ रहा है और हमारा संबंध अलकायदा से जोड़ा जा रहा है जिनसे हमारा कभी कोई संबंध नहीं रहा है। ज्ञातव्य है कि ईरान और अमेरिका में दिन-प्रतिदिन तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने दावा किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसको पंगु बनाने का प्रयास किया था मगर अमेरिका के ये प्रयास विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने शाह ईरान जैसे जालिम तानाशाह का खात्मा कर दिया था। अब हम अमेरिकी तानाशाह का सफाया करके ही दम लेंगे। अमेरिका की साजिश के बावजूद अपनी आर्थिक नीति से ईरान विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।

अन्य

मुस्लिम द्वारा शिव मंदिर के निर्माण का उद्घाटन

इंकलाब (13 जनवरी) के अनुसार दिल्ली में रानी झांसी रोड पर प्राचीन शिव मंदिर के निर्माण कार्य का उद्घाटन गुलफाम कुरैशी द्वारा किया गया। इस समारोह में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक डॉ. इंद्रेश कुमार ने विशेष रूप से भाग लिया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस मंदिर के निर्माण कार्य में मुसलमान भी बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं से अपील की कि वे भी मस्जिदों के निर्माण कार्य में बढ़-चढ़कर भाग लें ताकि हिन्दू मुस्लिम सद्भावना बनी रहे। उन्होंने हिंदुओं से यह भी आग्रह किया कि वे मुसलमानों की उपासना स्थलों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करें ताकि राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भावना और मानवता बनी रही। उन्होंने कहा कि हालांकि आज हालात बहुत खराब हैं। मगर फिर भी इनमें सुधार लाया जा सकता है। अगर विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहारों को इक्ट्ठा मनाएं। तभी दिलों में पैदा की गई दूरियों को दूर किया जा सकता है।

इस अवसर पर गुलफाम कुरैशी ने कहा कि मैं मंदिर के निर्माण में इसलिए भाग ले रहा हूं क्योंकि मुझे इस्लाम ने ऐसा ही सिखाया है। इस्लाम में किसी भी धर्म को बुरा कहने की शिक्षा नहीं दी जाती है और सभी धर्मों का सम्मान करने और उनके उपासना स्थलों को सुरक्षा प्रदान करने का सबक दिया जाता है। यही मानवता है। उन्होंने कहा कि हमारी सभ्यता हजारों साल पुरानी गंगा-जमुनी सभ्यता है जिसको बचाए रखना हमलोगों का कर्तव्य है। इस कार्यक्रम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हाफिज मोहम्मद साबरीन, डॉ. इमरान चौधरी, सिराज कुरैशी, खुर्शीद राजा आदि ने भी भाग लिया।

तुर्की में पूर्व जनरलों को उम्र कैद

इंकलाब (1 जनवरी) के अनुसार तुर्की की एक अदालत ने 2016 के असफल विद्रोह में भाग लेने के कारण एक दर्जन के लगभग पूर्व सैनिक जनरलों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कुल 132 लोगों को उम्रकैद की सजा दी गई है जिनका संबंध तुर्की की थल सेना से है। इस मुकदमें की सुनवाई 2017 में शुरू हुई थी। पूर्व सैनिक जनरलों को कठोर दंड दिया गया है। उन्हें भविष्य में पेरोल पर कभी रिहा नहीं किया जाएगा और पूरा जीवन उम्रकैद में ही काटना पड़ेगा। ज्ञातव्य है कि 2016 में राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का तख्ता पलटने का सेना ने प्रयास किया था जो कि विफल रहा। इसमें 500 से अधिक लोग मारे गए थे।

अमेरिका द्वारा अरब देशों को अस्त्र–शस्त्रों की बिक्री

इंकलाब (1 जनवरी) के अनुसार अमेरिकी कांग्रेस ने अमेरिकी प्रशासन को कुवैत, सऊदी अरब और मिस्र को 4.8 बिलियन डॉलर अस्त्र-शस्त्र बेचने की अनुमति दे दी है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी ने इन देशों को चार अरब 85 करोड़ 95 लाख डॉलर के मूल्य के सैनिक उपकरणों को बेचने की अनुमति दी है। इनमें लड़ाकू विमान, हेलिकॉप्टर, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल आदि शामिल है। मिस्र को वहां के राष्ट्रपति के विमान की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा कवच बेचने की अनुमति भी दी गई है। अस्त्र-शस्त्रों की बिक्री एक महीने के भीतर शुरू हो जाएगी।

विदेशी तब्लीगियों की स्वदेश वापसी का रास्ता साफ

इंकलाब (14 जनवरी) के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान देश में तब्लीगी जमात से संबंधित जो सैकड़ों विदेशी गिरफ्तार किए गए थे अब उनके स्वदेश लौटने का रास्ता साफ हो गया है। ज्ञातव्य है कि कोरोना महामारी एक्ट के तहत तब्लीगी जमात से संबंधित जिन विदेशी लोगों को गिरफ्तार किया गया था लगभग सभी मामलों में सरकार उनके खिलाफ न्यायालयों में मुकदमें सिद्ध करने में विफल रही है। इसलिए न्यायालयों ने उन्हें बरी कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के वकील फैसल अयूबी ने बताया कि तब्लीगियों को न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था और उन्हें स्वदेश वापस जाने की अनुमति भी दे दी गई थी मगर सीआरपीसी की धारा 337ए में यह प्रावधान है कि अगर कोई विदेशी न्यायालय से बरी हो जाता है तो उसे छह महीने के लिए इस बात की जमानत देनी पड़ती है कि अगर किसी ने कोई रिट याचिका दायर की तो उसे न्यायालय में पेश होना पड़ेगा। यही कारण है कि न्यायालय से बरी होने के बावजूद भी काफी तब्लीगी जमात वाले विदेशी स्वदेश वापस नहीं लौट पाए हैं। क्योंकि सरकार ने उन्हें एनओसी परमिट नहीं दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस कठिनाई को देखते हुए यह आदेश दिया है कि ये विदेशी मूल के लोग न्यायालय में शपथपत्र दाखिल करके स्वदेश लौट सकते हैं।

इजरायल जाने से इनकार करने पर विमान चालक निलंबित

इंकलाब (14 जनवरी) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात की एयरलाइंस के एक चालक ने विमान को इजरायल ले जाने से इनकार कर दिया था जिस पर उसे निलंबित कर दिया गया है। यह चालक ट्यूनीशिया का रहने वाला है। मोनेम साहिब अल-तबा नामक इस चालक ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है और अल्लाह ही मेरा मददगार है। उसने कहा कि मैं अनुशासन कमेटी के सामने पेश होउंगा जो मेरे निलंबन के बारे में फैसला करेगी। ट्यूनीशिया के समाचारपत्रों ने विमान चालक के इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा है कि उसका यह फैसला सरासर जायज है और वह इस बात का प्रमाण है कि फिलिस्तीन की समस्या ट्यूनीशिया के हर नागरिक के हृदय में जीवित है।

कुवैत के मंत्रिमंडल का त्यागपत्र

सियासत (7 जनवरी) के अनुसार कुवैत के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद ने अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र कुवैत के अमीर को पेश कर दिया है। समाचारपत्रों के अनुसार मंत्रियों के चयन में हुए विवाद के कारण उन्हें यह त्यागपत्र देना पड़ा है। ज्ञातव्य है कि एक महीने पूर्व इस मुद्दे पर सरकार और संसद के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था। नए अमीर शेख नवाफ अल-अहमद के लिए यह बड़ी चुनौती है जिन्होंने छह महीने पूर्व ही अमीर के रूप में पदभार संभाला था। तेल उत्पादक देशों के दबाव के कारण कुवैत को तेल के उत्पादन में काफी कटौती करनी पड़ी है जिसके कारण देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। रही सही कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि अमीर मंत्रिमंडल का त्यागपत्र स्वीकार करेंगे या नहीं।

RNI No. DELHI/2017/72722

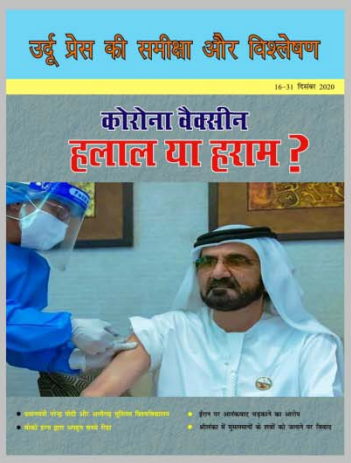

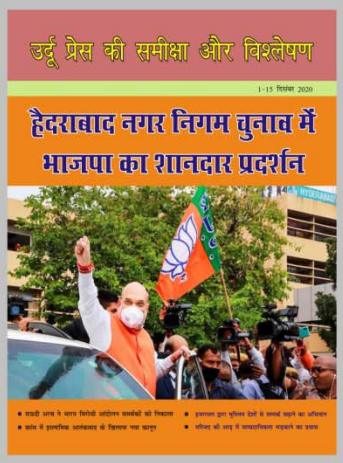

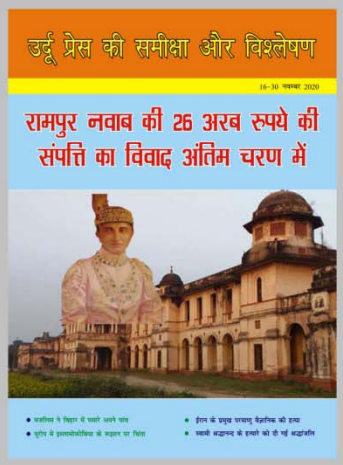

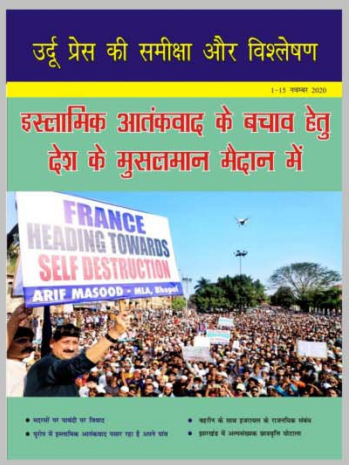

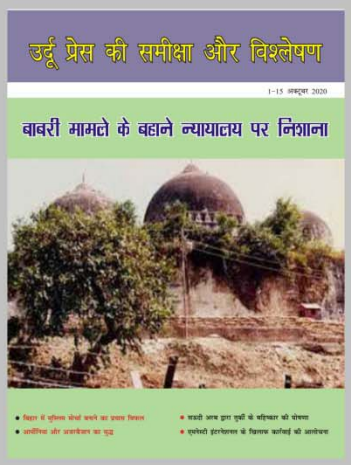

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018, फैक्स : 011-46089365
ई-मेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com, वेबसाइट : www.ipf.org.in